मैसर्स सोम दत्त बिल्डर्स लि.

बनाम

केरल राज्य (सिविल अपील संख्या 3089, 2006)

17 सितम्बर 2009

[तरुण चटर्जी और आर.एम. लोधा, जे.जे.]

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996:

धारा 31(3) - मध्यस्थ पंचाट - मध्यस्थ अधिकरण को पंचाट के समर्थन में कारण बताने की आवश्यकता है - तथ्यों पर, निष्कर्ष तक पहुंचने वाली विचार प्रक्रिया को प्रतिबिंबित करने के लिए पंचाट में कोई कारण नहीं दर्शाया गया है - मामला एडीजे को भेजा जाएगा जो पहले पंचाट को फैसले के समर्थन में कारण बताने के लिए ट्रिब्यूनल भेजेंगे - इसके बाद एडीजे सुनवाई और आपत्तियों को आगे बढ़ाएंगे।

पार्टियों ने कार्य अनुबंध में प्रवेश किया। अनुबंध के तहत ठेकेदार को बयालीस महीने के अंदर काम पूरा करना था. तय अवधि में काम पूरा नहीं हो सका. कार्य पूरा करने का समय दो अवसरों पर बढ़ाया गया; कुल मिलाकर 25 महीने तक। ठेकेदार का मामला यह था कि समय का विस्तार उनकी किसी भी गलती के कारण नहीं था और वास्तव में उन्हें कोचीन में साइट कार्यालय जारी रखना था; कि उन्होंने कोचीन में अपने काम के

संबंध में अतिरिक्त व्यय भी किया और करोड़ों रुपये की मशीनरी के संबंध में उपकरण स्वामित्व शुल्क के लिए अतिरिक्त व्यय भी कार्य के लिए नियोजित किया गया। इसलिए, ठेकेदार ने इंजीनियर के समक्ष विभिन्न मदों के तहत दावे उठाए। ठेकेदार के मुताबिक इंजीनियर ने क्लेम नंबर 1 के संबंध में निर्णय लिया परन्तु उक्त निर्णय को क्रियान्वित नहीं किया गया तथा अन्य दावों के संबंध में भी कोई निर्णय नहीं लिया गया। मामला मध्यस्थता के लिए भेजा गया। मध्यस्थ अधिकरण ने अपना पंचाट सुनाया। राज्य ने मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 34 के तहत जिला न्यायाधीश के समक्षयाचिका दायर की जिसको इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि विभिन्न शीर्षकों के तहत दावों की अनुमति के लिए मध्यस्थ अधिकरण द्वारा पर्याप्त कारण दर्ज किए गए थे।

उच्च न्यायालय ने आंशिक रूप से अपील को स्वीकार किया और दावा संख्या 1 और 4बी से संबंधित पंचाट को इस आधार पर रद्द कर दिया कि उसके निष्कर्षों में सहायक कारण नहीं थे, जो मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 28(3) और 31(3) का उल्लंघन है। दोनों पक्षों ने अपील दायर की।

अपीलों का निपटारा करते हुए मामले को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, न्यायालय के पास भेज कर अभिनिर्धारित किया गया।

1.1. पंचाट के अवलोकन से पता चला कि दावा संख्या 1 और 4बी के समर्थन में कोई कारण नहीं थे। मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 31(3) में कहा गया है कि मध्यस्थता पंचाट उन कारणों को बताएगा जिन पर यह आधारित है, जब तक कि - (ए) पार्टियां इस बात पर सहमत न हों कि कोई कारण नहीं दिया जाना चाहिए या (बी) पंचाट धारा 30 के तहत एक मध्यस्थ पंचाट नहीं है। यह विवाद में नहीं है कि वर्तमान मामला खंड (ए) और (बी) के अंतर्गत नहीं आता है। इन परिस्थितियों में, मध्यस्थ अधिकरण के लिए दावा संख्या 1 और 4बी के संबंध में अपने फैसले के समर्थन में कारण बताना अनिवार्य था। विधायी आदेश के अनुसार, अब मध्यस्थ अधिकरण के लिए पंचाट के समर्थन में कारण बताना आवश्यक है। 1996 का अधिनियम UNCITRAL मॉडल कानून पर आधारित है जिसमें उन कारणों को बताने का प्रावधान है जिन पर पंचाट आधारित है। [पैरा 20 और 21] [622-जी-एच; 623-ए-सी]

भारत संघ बनाम मोहन लाल कपूर **(1973) 2 एससीसी 836**; वूलकोम्बर्स ऑफ इंडिया लिमिटेड बनाम वूलकोम्बर्स वर्कर्स यूनियन और दूसरा एआईआर **1973 एससी 2758**; एस.एन. मुखर्जी बनाम भारत संघ **(1990) 4 एससीसी 594**; दिल्ली इलेक्ट्रिक सप्लाई अंडरटेकिंग बनाम विक्टर केबल इंडस्ट्रीज लिमिटेड एवं अन्य **2006 (1) अरब। एलआर- 297 (दिल्ली)**;

एमएस। कुमार कंस्ट्रक्शन कंपनी बनाम दिल्ली विकास प्राधिकरण एवं अन्य। **64 (1966) डीएलटी 553, को संदर्भित किया।**

1.2. धारा 31(3) के तहत पंचाट के समर्थन में कारणों की आवश्यकता कोई खाली औपचारिकता नहीं है। यह मध्यस्थ अधिकरण द्वारा विवाद पर निष्पक्ष और वैध विचार की गारंटी देता है। यह सच है कि मध्यस्थ अधिकरण से न्यायालय की तरह निर्णय लिखने की अपेक्षा नहीं की जाती है और न ही उससे अपने निष्कर्षों के समर्थन में विस्तार से और विस्तृत कारण देने की अपेक्षा की जाती है, लेकिन केवल पक्षों की दलीलों पर ध्यान देना या दस्तावेजों का संदर्भ लेना उन कारणों का विकल्प नहीं है जो मध्यस्थ अधिकरण देने के लिए बाध्य है. ये चाहे कितने भी संक्षिप्त क्यों न हों, पंचाट में कारणों का उल्लेख अवश्य किया जाना चाहिए क्योंकि यह किसी विशेष निष्कर्ष तक ले जाने वाली विचार प्रक्रिया को प्रतिबिंबित करेगा। धारा 31(3) की आवश्यकता को पूरा करने के लिए, कारण उस मध्यस्थ अधिकरण द्वारा बताया जाना चाहिए जिस पर पंचाट आधारित है; कारणों की कमी ऐसे पंचाट को कानूनी रूप से त्रुटिपूर्ण बना देगी। यह नहीं कहा जा सकता है कि उच्च न्यायालय यह देखने में गलत था कि मध्यस्थ अधिकरण द्वारा कोई कारण नहीं बताया गया था कि नियोक्ता द्वारा साढे 18 महीने के लिए बढ़ाई गई पूर्णता की अवधि उन कारणों से थी जिसके लिए दावेदार जिम्मेदार नहीं थे। हालाँकि, उच्च न्यायालय को मध्यस्थ

अधिकरण को कारण बताने का अवसर देना चाहिए था। दावा संख्या 5 के तहत पंचाट दावा संख्या 1. से संबंधित है। दावा क्रमांक 6 पर आपत्तियां को अतिरिक्त जिला न्यायाधीश द्वारा पुनः जांच भी कीया जा सकता है। पंचाट के खिलाफ केरल राज्य की याचिका को दावा संख्या 1, 4बी, 5 और 6. के संबंध में आपत्तियों पर नए सिरे से सुनवाई और विचार के लिए अतिरिक्त जिला न्यायाधीश की फाइल में बहाल कर दिया गया है। हालाँकि, अतिरिक्त जिला न्यायाधीश पहले दावा संख्या 1 और 4बी के समर्थन में अपने कारण बताने के लिए पंचाट अधिकरण को पंचाट भेजेंगे। और मध्यस्थ अधिकरण से कारण प्राप्त होने के बाद आपत्तियों की सुनवाई और निपटान के लिए आगे बढ़ेंगे। [पैरा 25, 27 और 28] [624-डी-एच; 625-ए-एफ; 626-ए-सी]

केस कानून संदर्भ:

(1973) 2 एससीसी 836	संदर्भित	पैरा 21
एआईआर 1973 एससी 2758	संदर्भित	पैरा 22
(1990) 4 एससीसी 594	संदर्भित	पैरा 23
2006 (1) अरब। एलआर-297	संदर्भित	पैरा 24
64 (1966) डीएलटी 553	संदर्भित	पैरा 25

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील नं. 3089/2006

एर्नाकुलम में केरल उच्च न्यायालय के 2005 की मध्यस्थता अपील संख्या 16 में पारित निर्णय और आदेश दिनांक 3.6.2005 से।

के साथ

सी.ए. 2006 की संख्या 3090।

अपीलकर्ता की ओर वी.ए. से मोहता, अरविंद मिनोचा, वीना मिनोचा और नीलकांत नायक।

प्रतिवादी की ओर से टी.एल.वी. अय्यर, जी. प्रकाश और बी. आनंद।

न्यायालय का निर्णय न्यायाधीश **आर.एम. लोधा जे. के** द्वारा पारित किया गया -

1. विशेष अनुमति द्वारा ये दो अपीलें केरल उच्च न्यायालय द्वारा पारित 3 जून 2005 के निर्णय और आदेश से उत्पन्न हुई हैं और इसलिए उनकी एक साथ सुनवाई की गई और इस निर्णय द्वारा उनका निपटारा किया जा रहा है।

2. मुख्य अभियंता, राष्ट्रीय राजमार्ग, लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए केरल राज्य ने मैसर्स सोम दत्त बिल्डर्स लिमिटेड (संक्षेप में, 'ठेकेदार') को राष्ट्रीय राजमार्ग-47 के सड़क कार्य से संबंधित एक अनुबंध दिया। । ये कार्य थे: (i) अलवे-विटीला को चार लेन का बनाना

और सुदृढ़ीकरण करना ;(ii) विट्टिला-अरूर को चार लेन का बनाना और मजबूत बनाना और (iii) अरूर-चेरथला को चार लेन का बनाना। अनुबंध की विशेष और सामान्य शर्तों (क्रमशः धारा IV और III) में उल्लिखित नियम और शर्तें अनुबंध में निर्दिष्ट शर्तों का अभिन्न अंग थीं। अनुबंध के तहत ठेकेदार को बयालीस महीने के भीतर काम पूरा करना था। तय अवधि में काम पूरा नहीं हो सका, यह विवाद का विषय नहीं है। यह भी एक स्वीकृत स्थिति है कि कार्य पूरा करने का समय दो अवसरों पर बढ़ाया गया था; कुल मिलाकर 25 महीने तक। ठेकेदार का मामला यह है कि समय का विस्तार उनकी किसी गलती के कारण नहीं था और वास्तव में उन्हें कोचीन में साइट कार्यालय जारी रखना था; कि उन्होंने कोचीन में अपने काम के संबंध में अतिरिक्त व्यय भी किया और करोड़ों रुपये की मशीनरी के संबंध में उपकरण स्वामित्व शुल्क के लिए अतिरिक्त व्यय भी कार्य के लिए नियोजित किया गया। इसलिए, ठेकेदार ने 22 फरवरी, 1998 को इंजीनियर के समक्ष विभिन्न मदों के तहत दावे उठाए। ठेकेदार के अनुसार, इंजीनियर ने दावा संख्या 1 के संबंध में निर्णय लिया लेकिन उक्त निर्णय लागू नहीं किया गया और अन्य दावों के संबंध में, कोई निर्णय नहीं लिया गया जिससे ठेकेदार को विवाद को मध्यस्थता के संदर्भ में लेने की आवश्यकता हुई।

3. 11 जनवरी, 1999 को तीन मध्यस्थों को शामिल करते हुए एक मध्यस्थ अधिकरण का गठन किया गया और ठेकेदार के सभी दावों को मध्यस्थ अधिकरण के पास निर्णय के लिए भेजा गया।

4. 20 मार्च 1999 को ठेकेदार ने मध्यस्थ अधिकरण के समक्ष सहायक दस्तावेजों के साथ अपना दावा प्रस्तुत किया। दावा संख्या 1 ठेकेदार द्वारा उन कारणों के लिए विस्तारित प्रवास के कारण अतिरिक्त लागत से संबंधित है जिनके लिए वें जिम्मेदार नहीं हैं। दावा संख्या 1 दावे के विवरण के अनुसार तीन शीर्षकों के अंतर्गत है, अर्थात्; (i) उपकरण स्वामित्व शुल्क रु. 10,43,49,369/-; (ii) साइट ओवर-हेड्स के लिए रुपये 9,16,31,609/-; और (iii) प्रधान कार्यालय ओवर-हेड्स रु. 2,45,68,507/- कुल रु. 22.05,40,405/-. दावा संख्या 4 बी राशि रु. 3,33,924.69 कुएं की नींव से खुली नींव में परिवर्तन के कारण होने वाला अतिरिक्त व्यय से सम्बंधित है। दावा संख्या 5 कुल मिलाकर रु. 2,85,93,625/- रुपये विभिन्न स्थानीय यूनियनों की हड़ताल, बंद और पुलिस तथा अन्य प्राधिकारियों के हस्तक्षेप के कारण हुए नुकसान की भरपाई के लिए ठेकेदार द्वारा उठाया गया। दावा संख्या 6 रुपये 2,46,817/- ठेकेदार द्वारा 10% की दर से योगदान किए गए भविष्य निधि की प्रतिपूर्ति के लिए ठेकेदार द्वारा उठाया गया।

5. 30 अक्टूबर 1999 को मध्यस्थ अधिकरण के समक्ष सहायक दस्तावेजों के साथ राज्य सरकार की ओर से बचाव का बयान प्रस्तुत किया गया था।

6. ठेकेदार ने 27 नवंबर, 1999 को अपना प्रत्युत्तर प्रस्तुत किया, जबकि राज्य सरकार द्वारा बचाव का एक अतिरिक्त बयान 17 मार्च, 2001 को दायर किया गया था।

7. मध्यस्थ अधिकरण ने 20 दिसंबर, 2003 को अपना फैसला सुनाया। जहां तक दावा संख्या 1 का संबंध है, मध्यस्थ अधिकरण ने रुपये 7,61,41,460/- की राशि प्रदान की। मध्यस्थ अधिकरण ने रुपये 2,86,985.23 की राशि दावा संख्या 4 बी के लिए; दावा संख्या 5 के लिए रु. 1,00,26,900/- का और दावा संख्या 6. के लिए रु. 2,31,821/- फैसला सुनाया । अन्य दावों से निपटना आवश्यक नहीं है क्योंकि वे इन दो अपीलों की विषय वस्तु नहीं हैं।

8. मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (संक्षेप में, 'अधिनियम, 1996') की धारा 34 के तहत एक याचिका केरल राज्य द्वारा जिला न्यायाधीश, एर्नाकुलम के समक्ष 20 दिसंबर, 2003 के फैसले को रद्द करने के लिए अन्य बातों के साथ-साथ इस आधार दायर की गई थी कि यह पंचाट कोई तर्कसंगत पंचाट नहीं था।

9. द्वितीय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, एर्नाकुलम, जिनके पास मामला स्थानांतरित किया गया था, ने अपने फैसले और आदेश दिनांक 23 फरवरी, 2005 द्वारा केरल राज्य द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया। उन्होंने माना कि प्रत्येक दावे को स्वीकार करने के लिए मध्यस्थ अधिकरण द्वारा पर्याप्त कारण दर्ज किए गए थे।

10. केरल राज्य ने तब अधिनियम, 1996 की धारा 34 के तहत उनकी याचिका को खारिज करने वाले द्वितीय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के फैसले और आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील दायर की।

11. डिवीजन बेंच ने अपील पर सुनवाई की और 3 जून, 2005 को अपने फैसले में अपील को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया और दावा संख्या 1 और 4 बी से संबंधित पंचाट को इस आधार पर रद्द कर दिया कि उसके निष्कर्षों में समर्थन में कारण नहीं हैं जो अधिनियम, 1996 की धारा 28(3) और 31(3) का उल्लंघन हैं। डिवीजन बेंच ने दावों 7 बी और 7 सी के तहत दावा किए गए दिए गए ब्याज को भी रद्द कर दिया। .

12. दोनों पक्ष डिविजन बेंच के फैसले से व्यथित हैं। 2006 की सिविल अपील संख्या 3089 को उक्त निर्णय से व्यथित ठेकेदार द्वारा इस हद तक पेश किया गया दावा संख्या 1 और 4 बी से संबंधित पंचाट को खारिज कर दिया गया है जबकि 2006 की सिविल अपील संख्या 3090

दावा संख्या 5 और 6 से संबंधित पंचाट से असंतुष्ट केरल राज्य के निवेदन पर है।.

13. यह उचित है कि बहस के दौरान विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा संदर्भित अनुबंध की शर्तों के कुछ खंडों पर सबसे पहले हमारा ध्यान जाता है।

14. खंड 1.1 (ए)(i) 'नियोक्ता'को इस प्रकार परिभाषित करता है:

> "नियोक्ता"का अर्थ है राज्य (भारत) के राज्यपाल या कार्यालय में उनके उत्तराधिकारी और नियुक्तियाँ। परियोजना का प्रभारी मुख्य अभियंता परियोजना का कार्यभारी होगा।"

15. खंड 1.1 (ए)(iv) 'इंजीनियर'को इस प्रकार परिभाषित करता है:

> "इंजीनियर"का अर्थ है लोक निर्माण विभाग का अधीक्षण अभियंता, जिसे इस अनुबंध के परियोजना निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है या नियोक्ता द्वारा नियुक्त कोई अन्य व्यक्ति, जिसे ठेकेदार को लिखित नोटिस द्वारा इंजीनियर के कार्य करने हेतु प्रतिस्थापन किया है।"

16. दावों की प्रक्रिया खंड 53.1 से 53.5 में निर्धारित है जो इस प्रकार है:

> “53.1. अनुबंध के किसी भी अन्य प्रावधान के बावजूद, यदि ठेकेदार इन शर्तों के किसी खंड के अनुसार या अन्यथा

किसी अतिरिक्त भुगतान का दावा करना चाहता है, तो उसे अपने इरादे की सूचना नियोक्ता को एक प्रति के साथ, दावे को उत्पन्न करने वाली घटना सबसे पहले सामने आई है से 28 दिनों के भीतर इंजीनियर को देनी होगी।

53.2. उप-खंड 53.1 में निर्दिष्ट घटना के घटित होने पर, ठेकेदार ऐसे समसामयिक रिकॉर्ड रखेगा जो किसी भी दावे का समर्थन करने के लिए उचित रूप से आवश्यक हो सकता है जिसे वह बाद में करना चाहेगा। नियोक्ता के दायित्व को आवश्यक रूप से स्वीकार किए बिना, इंजीनियर, उप-खंड 53.1 के तहत एक नोटिस प्राप्त होने पर, ऐसे समसामयिक रिकॉर्ड का निरीक्षण करेगा और ठेकेदार को किसी भी अन्य समसामयिक रिकॉर्ड को रखने का निर्देश दे सकता है जो उचित हो और जिस नोटिस के दावे के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है दिया गया है। ठेकेदार इंजीनियर को इस उप-खंड के अनुसार रखे गए सभी रिकॉर्डों का निरीक्षण करने की अनुमति देगा और जब भी इंजीनियर निर्देश देगा, उसे उसकी प्रतियां उपलब्ध कराएगा।

53.3. उप-खंड 53.1 के तहत नोटिस देने के 28 दिनों या ऐसे अन्य उचित समय के भीतर, जिस पर इंजीनियर

सहमत हो, ठेकेदार इंजीनियर को दावा की गई राशि और जिस आधार पर दावा आधारित है, उसका विस्तृत विवरण देते हुए एक खाता भेजेगा। जहां दावे को जन्म देने वाली घटना का निरंतर प्रभाव होता है, ऐसे खाते को एक अंतरिम खाता माना जाएगा और ठेकेदार, ऐसे अंतराल पर, जैसा कि इंजीनियर को उचित रूप से आवश्यकता हो, दावे की संचित राशि देते हुए आगे अंतरिम खाते भेजेगा और कोई अन्य आधार जिस पर यह आधारित है। ऐसे मामलों में जहां अंतरिम खाते इंजीनियर को भेजे जाते हैं, ठेकेदार को घटना के परिणामस्वरूप होने वाले प्रभावों की समाप्ति के 28 दिनों के भीतर अंतिम विवरण भेजना होगा। यदि इंजीनियर द्वारा ऐसा करने की अपेक्षा की जाती है, तो ठेकेदार इस उप-खंड के अनुसार इंजीनियर को भेजे गए सभी खातों की प्रतिलिपि नियोक्ता को देगा।

53.4. यदि ठेकेदार किसी भी दावे के संबंध में इस खंड के किसी भी प्रावधान का पालन करने में विफल रहता है, जिसे वह करना चाहता है, तो उसके संबंध में भुगतान का उसका अधिकार उप खंड 67.3 के अनुसार नियुक्त दावे का आकलन करने वाले इंजीनियर या किसी मध्यस्थ या मध्यस्थों की

राशि को समकालीन रिकॉर्ड द्वारा सत्यापित माना जाता है से अधिक नहीं होगा। -(उप-खंड 53.2 और 53.3 के तहत आवश्यक ऐसे रिकॉर्ड इंजीनियर के ध्यान में लाए गए थे या नहीं तब भी)

53.5. ठेकेदार खंड 60 के अनुसार इंजीनियर द्वारा प्रमाणित किसी भी अंतरिम भुगतान में किसी भी दावे के संबंध में ऐसी राशि शामिल करने का हकदार होगा, जैसा कि इंजीनियर, नियोक्ता और ठेकेदार के साथ उचित परामर्श के बाद, ठेकेदार के देय पर विचार कर सकता है, बशर्ते कि ठेकेदार ने इंजीनियर को देय राशि निर्धारित करने में सक्षम बनाने के लिए पर्याप्त विवरण प्रदान किया है। यदि ऐसे विवरण पूरे दावे को प्रमाणित करने के लिए अपर्याप्त हैं, तो ठेकेदार दावे के ऐसे हिस्से के संबंध में भुगतान का हकदार होगा, क्योंकि ऐसे विवरण इंजीनियर की संतुष्टि के लिए पर्याप्त हो सकते हैं। इंजीनियर इस उप-खंड के तहत किए गए किसी भी निर्धारण के बारे में ठेकेदार को सूचित करेगा, जिसकी एक प्रति नियोक्ता को भी भेजी जाएगी।"

17. विवाद के निपटारे के संबंध में, प्रासंगिक खंड 67.1 से 67.4 हैं जो निम्नानुसार प्रदान करते हैं: "

67.1. यदि नियोक्ता और ठेकेदार के बीच अनुबंध या कार्यों के निष्पादन के संबंध में या उससे उत्पन्न किसी भी प्रकार का कोई विवाद उत्पन्न होता है, चाहे कार्यों के निष्पादन के दौरान या उनके पूरा होने के बाद और चाहे अनुबंध की समाप्ति से पहले या अस्वीकृति या अन्य के बाद, जिसमें इंजीनियर की किसी भी राय, निर्देश, निर्धारण, प्रमाण पत्र या मूल्यांकन के बारे में कोई भी विवाद शामिल है, विवादित मामला, सबसे पहले, इंजीनियर को लिखित रूप में भेजा जाएगा, जिसकी एक प्रति दूसरे पक्ष को दी जाएगी। इस तरह के संदर्भ में यह बताया जाएगा कि यह इस खंड के अनुसार बनाया गया है। जिस दिन उसे ऐसा संदर्भ प्राप्त हुआ उसके चौरासीवें दिन के पहले इंजीनियर को अपने निर्णय की सूचना नियोक्ता और ठेकेदार को देनी होगी। इस तरह के निर्णय में यह बताया जाएगा कि यह इस खंड के अनुसार किया गया है।

जब तक कि अनुबंध को पहले ही अस्वीकार या समाप्त नहीं कर दिया गया है, ठेकेदार, हर मामले में, पूरे परिश्रम के साथ काम करना जारी रखेगा और ठेकेदार और नियोक्ता इंजीनियर के ऐसे हर निर्णय को तुरंत प्रभावी करेंगे जब तक कि एक सौहार्दपूर्ण समझौते या एक मध्यस्थ पंचाट में उसे संशोधित किया गया न हो।

यदि नियोक्ता या ठेकेदार इंजीनियर के किसी निर्णय से असंतुष्ट है, या यदि इंजीनियर संदर्भ प्राप्त होने के दिन के चौरासीवें दिन या उससे

पहले अपने निर्णय की सूचना देने में विफल रहता है, तो या तो नियोक्ता या ठेकेदार, उस दिन के बाद सत्तरवें दिन या उससे पहले, जिस दिन उसे इस तरह के निर्णय की सूचना प्राप्त हुई थी, या उस दिन के सत्तरवें दिन से पहले, जिस दिन 84 दिनों की उक्त अवधि समाप्त हो गई, जैसा भी मामला हो, विवादित मामले के संबंध में मध्यस्थता शुरू करने के उसके इरादे के बारे में इंजीनियर को जानकारी के लिए एक प्रति के साथ दूसरे पक्ष को नोटिस दे सकता है, जैसा कि इसमें इसके बाद प्रदान किया गया है। इस तरह का नोटिस इस तरह के विवाद के संबंध में, जैसा कि इसके बाद प्रदान किया गया है, मध्यस्थता शुरू करने के लिए पार्टी का अधिकार स्थापित करेगा और, उप-खंड 67.4 के अधीन, उसके संबंध में कोई भी मध्यस्थता तब तक शुरू नहीं की जा सकती जब तक कि ऐसा नोटिस नहीं दिया जाता है। यदि इंजीनियर ने विवाद के मामले में अपने निर्णय की सूचना नियोक्ता और ठेकेदार को दे दी है और नियोक्ता या ठेकेदार द्वारा सत्तरवें दिन या उससे पहले ऐसे विवाद के संबंध में मध्यस्थता शुरू करने के इरादे की कोई सूचना नहीं दी गई है। जिस दिन पार्टियों को इंजीनियर से ऐसे निर्णय के बारे में नोटिस प्राप्त होगा, उक्त निर्णय अंतिम हो जाएगा और नियोक्ता और ठेकेदार पर बाध्यकारी होगा।

67.2.....

67.3.....

67.4. जहां न तो नियोक्ता और न ही ठेकेदार ने उप-खंड 67 1 में बताई गई अवधि के भीतर विवाद की मध्यस्थता शुरू करने के इरादे की सूचना दी है और संबंधित निर्णय अंतिम और बाध्यकारी हो गया है, कोई भी पक्ष, यदि दूसरा पक्ष ऐसे निर्णय का पालन करने में विफल रहता है, और उसके किसी भी अन्य अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उप-खंड 673 के अनुसार मध्यस्थता में विफलता का उल्लेख कर सकता है। उप-खंड 67.1 और 67.2 के प्रावधान ऐसे किसी भी संदर्भ पर लागू नहीं होंगे।

18. श्री वी.ए. ठेकेदार के विद्वान वरिष्ठ वकील मोहता ने प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय का यह मानना उचित नहीं था कि दावा संख्या 1 और 4 बी के संबंध में उनके पंचाट के समर्थन में मध्यस्थ अधिकरण द्वारा कोई कारण नहीं बताया गया है। उन्होंने 'नियोक्ता'और 'इंजीनियर'की परिभाषाओं का उल्लेख किया; खंड 7.1 ; परियोजना निदेशक की ओर से मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग को दिनांक 23 अप्रैल, 1998 का संचार (जो उनके अनुसार दावा संख्या 1 के संबंध में इंजीनियर का निर्णय है) और मुख्य अभियंता की ओर से दिनांक 11 मई, 1998 का संचार महानिदेशक (सड़क), भूतल (परिवहन), नई दिल्ली ने प्रस्तुत किया कि काम पूरा होने में देरी के लिए नियोक्ता ने ठेकेदार को जिम्मेदार नहीं माना है और इसलिए मध्यस्थ अधिकरण द्वारा दावा संख्या

1 के लिए पंचाट पारित करते समय कोई और कारण बताने की आवश्यकता नहीं है। श्री वी.ए. मोहता ने यह भी कहा कि उच्च न्यायालय ने दावा संख्या 4 बी के संबंध में पंचाट को रद्द करके गलती की है, क्योंकि मध्यस्थ अधिकरण द्वारा उक्त दावे के समर्थन में वैध कारण दिए गए हैं और उन्हें फैसले से ही स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। वैकल्पिक रूप से, विद्वान वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया कि यदि उच्च न्यायालय को लगता है कि फैसले के समर्थन में कोई कारण नहीं हैं, तो उसे अन्य कारण बताने के लिए मामले को मध्यस्थ अधिकरण को भेज देना चाहिए था। इस संबंध में, उन्होंने अधिनियम, 1996 की धारा 34(4) का संदर्भ दिया।

19. दूसरी ओर, श्री टी.एल.वी. लायर, प्रतिवादी के विद्वान वरिष्ठ वकील ने दावा संख्या 1 और 4 बी के संबंध में उच्च न्यायालय के दृष्टिकोण का समर्थन किया। हालाँकि, उन्होंने दावा संख्या 5 और 6 के संबंध में उच्च न्यायालय के दृष्टिकोण की आलोचना की और प्रस्तुत किया कि इन दोनों दावों के संबंध में पंचाट कारणों से समर्थित नहीं है और पंचाट उस हद तक कानूनी रूप से त्रुटिपूर्ण है।

20. यह सच है कि परियोजना निदेशक द्वारा मुख्य अभियंता, राष्ट्रीय राजमार्ग को 23 अप्रैल, 1998 को भेजा गया संचार ठेकेदार द्वारा 22 फरवरी, 1998 को प्रस्तुत दावा संख्या 1 से संबंधित है और उन्होंने 12 महीनों के लिए समग्र उपकरण स्वामित्व शुल्क और साइट ओवर-हेड की

सिफारिश की और आगे 13,01,42,462/- रुपये के दावे की सिफारिश की। यह भी देखा गया है कि मुख्य अभियंता (नियोक्ता) ने 11 मई, 1998 को महानिदेशक (सड़क), भूतल (परिवहन) मंत्रालय को लिखे अपने पत्र में परियोजना निदेशक के उक्त पत्र को खंड 67.1 के तहत एक 'निर्णय'के रूप में संदर्भित किया है। इंजीनियर द्वारा और भूतल (परिवहन) मंत्रालय से ठेकेदार के दावे का निपटान करने का अनुरोध किया गया। निस्संदेह, उपरोक्त दो दस्तावेजों को मध्यस्थ अधिकरण द्वारा पंचाट में संदर्भित किया गया है और मध्यस्थ अधिकरण ने अपने-अपने रुख के समर्थन में पार्टियों की ओर से दी गई दलीलों पर भी गौर किया है लेकिन इसके निष्कर्ष के समर्थन में कारण बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं हैं कि प्रतिवादी द्वारा ठेकेदार को जिम्मेदार नहीं ठहराए जाने वाले कारणों से पूरा होने की अवधि 18 = महीनों के लिए बढ़ा दी गई थी। पंचाट को ध्यान से पढ़ने के बाद, हम दावा संख्या 1 के समर्थन में कारण नहीं ढूंढ पाए। दावा संख्या 4 बी के लिए पंचाट के संबंध में स्थिति कोई बेहतर नहीं है। वास्तव में, उस दावे को देने के लिए कोई भी कारण नहीं बताया गया है।

21. धारा 31(3) आदेश देती है कि मध्यस्थ पंचाट उन कारणों को बताएगा जिन पर यह आधारित है, जब तक कि - (ए) पार्टियां इस बात पर सहमत न हों कि कोई कारण नहीं दिया जाना चाहिए या (बी) यह पंचाट धारा 30 के तहत एक मध्यस्थ पंचाट है। यह कि वर्तमान मामला

खंड (ए) और (बी) के अंतर्गत नहीं आता है, विवाद में नहीं है। इन परिस्थितियों में, मध्यस्थ अधिकरण के लिए दावा संख्या 1 और 4 बी के संबंध में अपने फैसले के समर्थन में कारण बताना अनिवार्य था। विधायी आदेश के अनुसार, अब मध्यस्थ अधिकरण के लिए पंचाट के समर्थन में कारण बताना आवश्यक है। यहां यह ध्यान रखना उचित है कि अधिनियम, 1996 UNCITRAL मॉडल कानून पर आधारित है जिसमें उन कारणों को बताने का प्रावधान है जिन पर पंचाट आधारित है। भारत संघ बनाम मोहन लाल कपूर (1973) 2 एससीसी 836[1]में, इस न्यायालय ने कहा, 'कारण उन सामग्रियों के बीच संबंध हैं जिन पर कुछ निष्कर्ष आधारित हैं और वास्तविक निष्कर्ष हैं।'

22. वूलकोम्बर्स ऑफ इंडिया लिमिटेड बनाम वूलकोम्बर्स वर्कर्स यूनियन और अन्य में, इस न्यायालय ने कहा:

> "...प्रारंभिक क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते समय न्यायिक और अर्ध-न्यायिक अधिकारियों द्वारा अपने निष्कर्षों के समर्थन में कारण देना विभिन्न कारणों से आवश्यक है। सबसे पहले, निष्कर्ष तक पहुंचने में अचेतन अनुचितता या मनमानी को रोकने के लिए इसकी गणना की जाती है।

1(1973) 2 एससीसी 836

कारणों की खोज ही प्राधिकरण को सतर्क कर देगी और निष्कर्ष में व्यक्तिगत पूर्वाग्रह या अनुचितता की अचेतन घुसपैठ की संभावना को कम कर देगी। प्राधिकारी ऐसे कारण सुझाएगा जिन्हें एक उचित व्यक्ति द्वारा उचित और वैध माना जाएगा और अप्रासंगिक या असंगत विचारों को त्याग दिया जाएगा..."

23. एस.एन. में मुखर्जी बनाम भारत संघ, संविधान पीठ ने कहा कि कारणों की रिकॉर्डिंग:

(i) प्राधिकारी द्वारा विचार की गारंटी देता है;

(ii) निर्णयों में स्पष्टता लाना; और

(iii) निर्णय लेने में मनमानी की संभावना को कम करता है।

24. ठेकेदार के विद्वान वरिष्ठ वकील ने दिल्ली इलेक्ट्रिक सप्लाई अंडरटेकिंग बनाम विक्टर केबल इंडस्ट्रीज लिमिटेड और अन्य के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय के एक फैसले का हवाला दिया और प्रस्तुत किया कि जहां मध्यस्थ ने मामले के तथ्यों का उल्लेख किया है और कुछ तर्क देखे हैं जो मध्यस्थ के विचार में राहत देने के लिए निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पर्याप्त थे, निर्णय को अनुचित नहीं कहा जा सकता है। उन्होंने मैसर्स कुमार कंस्ट्रक्शन कंपनी बनाम दिल्ली विकास प्राधिकरण एवं अन्य के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय के एक और फैसले का भी उल्लेख किया

जिसमें यह देखा गया है कि मध्यस्थ से विस्तृत निर्णय लिखने की अपेक्षा नहीं की जाती है और जहां मध्यस्थ ने वकील के तर्कों पर ध्यान दिया है, तो यह नहीं कहा जा सकता है कि मध्यस्थ पंचाट के लिए कारण बताने में विफल रहा।

25. धारा 31(3) के तहत पंचाट के समर्थन में कारणों की आवश्यकता कोई खाली औपचारिकता नहीं है। यह मध्यस्थ अधिकरण द्वारा विवाद पर निष्पक्ष और वैध विचार की गारंटी देता है। यह सच है कि मध्यस्थ अधिकरण से न्यायालय की तरह निर्णय लिखने की अपेक्षा नहीं की जाती है और न ही उससे अपने निष्कर्षों के समर्थन में विस्तार से और विस्तृत कारण देने की अपेक्षा की जाती है, लेकिन केवल पक्षों की दलीलों पर ध्यान देना या दस्तावेजों का संदर्भ लेना उन कारणों का विकल्प नहीं है जो मध्यस्थ अधिकरण देने के लिए बाध्य है। ये चाहे कितने भी संक्षिप्त क्यों न हों, पंचाट में कारणों का उल्लेख अवश्य किया जाना चाहिए क्योंकि यह किसी विशेष निष्कर्ष तक ले जाने वाली विचार प्रक्रिया को प्रतिबिंबित करेगा। धारा 31(3) की आवश्यकता को पूरा करने के लिए, कारण उस मध्यस्थ अधिकरण द्वारा बताया जाना चाहिए जिस पर पंचाट आधारित है; कारणों की कमी ऐसे पंचाट को कानूनी रूप से त्रुटिपूर्ण बना देगी।

हमने ऊपर जो चर्चा की है, उसमें यह नहीं कहा जा सकता है कि उच्च न्यायालय यह देखने में गलत था कि मध्यस्थ अधिकरण द्वारा कोई

कारण नहीं बताया गया है कि क्या नियोक्ता द्वारा 18 = महीने के लिए बढ़ायी गयी पूर्णता की अवधि उन कारणों से थी जिसके लिए दावा करने वाला जिम्मेदार नहीं था। हालाँकि, हमारे विचार में, उच्च न्यायालय को मध्यस्थ अधिकरण को कारण बताने का अवसर देना चाहिए था। यह पाठ्यक्रम अधिनियम की धारा 34(4) के तहत उपलब्ध है जो इस प्रकार है:

"1.....

2.....

3.....

4. अपास्त करने के लिए कोई आवेदन, उस तारीख से, जिसको आवेदन करने वाले पक्षकार ने माध्यस्थम् पंचाट प्राप्त किया था, या यदि अनुरोध धारा 33 के अधीन किया गया है तो उस तारीख से, जिसको माध्यस्थम् अधिकरण द्वारा अनुरोध का निपटारा किया गया था, तीन मास के अवसान के पश्चात् नही किया जाएगा : परन्तु यह कि जहां न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि आवेदक उक्त तीन मास की अविध के भीतर आवेदन करने से पर्याप्त कारण से निवारित किया गया था तो वह तीस दिन की

अतिरिक्त अवधि मे आवेदन ग्रहण कर सकेगा किन्तु इसके पश्चात् नही।"

26. दावेदार के विद्वान वरिष्ठ वकील ने हमें सूचित किया है कि मध्यस्थ अधिकरण का गठन करने वाले सभी तीन व्यक्ति उपलब्ध हैं और यदि कारणों को दर्ज करने के लिए पंचाट उन्हें भेजा जाता है, तो ऐसा करने में कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। यह प्रणाली हमें निष्पक्ष और उचित प्रतीत होता है।

27. दावा संख्या 5 के तहत पंचाट दावा संख्या 1 से संबंधित है। दावा क्रमांक 6 पर आपत्तियां की अब अतिरिक्त जिला न्यायाधीश द्वारा भी दोबारा जांच की जा सकती है क्योंकि धारा 34 के तहत याचिका उस अदालत की फाइल में बहाल की जा रही है।

28. तदनुसार, हम निम्नलिखित आदेश द्वारा इन दोनों अपीलों का निपटान करते हैं:

(i) उच्च न्यायालय के 3 जून 2005 के फैसले और द्वितीय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, एर्नाकुलम द्वारा पारित 23 फरवरी 2005 के फैसले को रद्द किया जाता है।

(ii) 20 दिसंबर 2003 के फैसले के खिलाफ केरल राज्य की याचिका (ओ.पी. अरब. 71/2004) को नए सिरे से दावा संख्या 1, 4 बी, 5 और 6

की सुनवाई और आपत्तियों पर विचार के लिए द्वितीय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, एर्नाकुलम की फाइल में बहाल किया जाता है।

(iii) हालाँकि, द्वितीय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, एर्नाकुलम पहले दावा संख्या 1 और 4 बी के समर्थन में अपने कारण बताने के लिए पंचाट अधिकरण को पंचाट भेजेंगे और मध्यस्थ अधिकरण से कारण प्राप्त होने के बाद आपत्तियों की सुनवाई और निपटान के लिए आगे बढ़ें।

(iv) पार्टियां अपना खर्चा स्वयं वहन करेंगी।

अपीलें निस्तारित।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास'की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी शांतनु सिंह खंगारोत (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।